International Relations

1. 2020 की तुलना में 2021 में 40 मिलियन अधिक लोगों ने खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

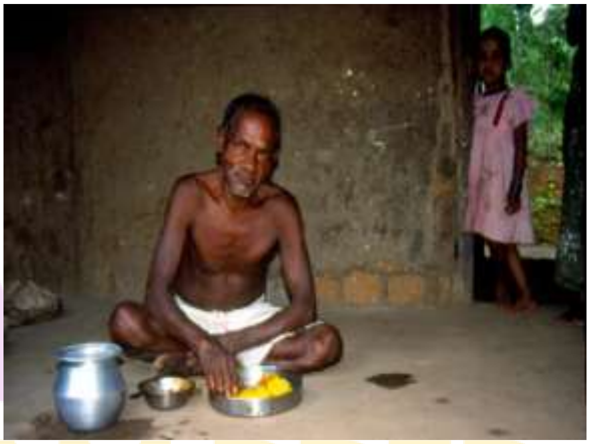

- **ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस (GNAFC)** की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 40 मिलियन अधिक लोगों ने संकट या बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया।
- **GNAFC** संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों का एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है जो एक साथ खाद्य संकट से निपटने के लिए काम कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इनमें से इथियोपिया, दक्षिणी मेडागास्कर, दक्षिण सूडान और यमन में आधे मिलियन से अधिक लोगों (570,000) को तीव्र खाद्य असुरक्षा के सबसे गंभीर चरण में वर्गीकृत किया गया।
- दस्तावेज़ ने दिखाया कि 53 देशों या क्षेत्रों में लगभग 193 मिलियन लोगों ने 2021 में संकट या बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया।

रिपोर्ट के अनुसार खाद्य असुरक्षा के लिए तीन मुख्य चालक थे:

- पहला संघर्ष था। रिपोर्ट 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले लिखी गई थी। लेकिन यह पाया गया कि संघर्ष ने 24 देशों / क्षेत्रों में 139 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा में मजबूर कर दिया। यह 2020 में 23 देशों / क्षेत्रों में 99 मिलियन से अधिक है।
- एक अन्य कारण मौसम की चरम सीमा थी, जिसने 2020 में 15 देशों / क्षेत्रों में 15.7 मिलियन से बढ़कर, आठ देशों / क्षेत्रों में 23 मिलियन से अधिक लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा में मजबूर कर दिया।

- तीसरा कारण आर्थिक झटके थे। 2021 में आर्थिक झटके के कारण 21 देशों / क्षेत्रों में 30 मिलियन से अधिक लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जो 2020 में 17 देशों / क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक लोगों से कम है।

स्रोत: DTE

2. RSF 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 8 पायदान गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है

चर्चा में क्यों?

- **रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF)** द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, **2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक** (20वें संस्करण) में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 180 देशों में से 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है।

प्रमुख बिंदु

- नेपाल को छोड़कर, भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान को 157वें, श्रीलंका को 146वें, बांग्लादेश को 162वें और म्यांमार को 176वें स्थान पर रखा गया है।
- नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 30 अंकों की बढ़त के साथ 76वें स्थान पर पहुंच गया है।
- इस साल **नॉर्वे (प्रथम),** डेनमार्क (दूसरा), स्वीडन (तीसरा), एस्टोनिया (चौथा) और फिनलैंड (पांचवां) ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि उत्तर कोरिया सूची में सबसे नीचे रहा।
- वैश्विक परिदृश्य के बारे में, RSF ने कहा कि 20वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से पता चलता है कि "ध्रुवीकरण" में दो गुना वृद्धि हुई है, जो सूचना अराजकता से बढ़ी है, यानी मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर विभाजन को बढ़ावा देता है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच ध्रुवीकरण भी।

स्रोत: HT

Important News: India

3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई, 2022 को कोपेनहेगन में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की।

प्रमुख बिंदु

- पेरिस में, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से आमने-सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में मुलाकात की।
- दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, नीली अर्थव्यवस्था, असैन्य परमाणु और लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सहयोग सहित द्विपक्षीय मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की।

नोट:

- अगस्त 2019, जून 2017, नवंबर 2015 और अप्रैल 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पांचवीं फ्रांस यात्रा है।
- दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2021 में G20 रोम शिखर सम्मेलन, जून 2019 में G20 ओसाका शिखर सम्मेलन और दिसंबर 2018 में G20 ब्यूनस आयर्स शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की।
- भारत और फ्रांस, जो 1998 से रणनीतिक साझेदार हैं, के बीच रक्षा, असैन्य परमाणु, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण, आतंकवाद का मुकाबला, लोगों से लोगों के बीच संबंधों में बहुआयामी साझेदारी है।
- भारत और फ्रांस नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** के संस्थापक सदस्य हैं।

स्रोत: TOI

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के अंतर्गत तीन एक जिला एक उत्पाद ब्रांड और पांच उत्पाद जारी किए गए

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना** के औपचारिककरण के अंतर्गत तीन **एक जिला एक उत्पाद (ODOP)** ब्रांड जारी किए।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने PMFME योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत चयनित 20 ODOP के 10 ब्रांड विकसित करने के लिए NAFED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 7 ODOP ब्रांड और 9 उत्पाद, 3 ODOP ब्रांड और 5 उत्पाद, जिनके नाम हैं: मधुरमिठास, अनारस, पिंड से और दो उत्पाद मसाला पेस्ट और लेमन हनी नए विकसित ब्रांड कश्मीरी मंत्र और मधुमंत्र के अंतर्गत सफलतापूर्वक जारी किए गए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के बारे में:

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया, PMFME योजना, एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म-उद्यम की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सेक्टर का औपचारिक रूप से प्रचार करना है, और किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, और उत्पादकों को उनके संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करते हैं।
- वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, इस योजना की परिकल्पना मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता करने के लिए है।

स्रोत: PIB

5. प्लास्टइंडिया (PLASTINDIA) 2023

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने **प्लास्टइंडिया (PLASTINDIA) 2023**-11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- डॉ मंडाविया ने कहा कि "ये प्रदर्शनियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक खिलाड़ियों को देश में आकर्षित करेंगी और विचारों और प्रौद्योगिकी को सीखने और आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगी"।
- भारत का पेट्रोकेमिकल उद्योग उच्च मांग वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक रहा है।
- भारत को अगले दशकों में पेट्रोकेमिकल्स में वृद्धिशील वैश्विक विकास में 10% से अधिक योगदान देने का अनुमान है।
- भारतीय रासायनिक उद्योग एक वैश्विक खिलाड़ी बन गया है और "मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड" दृष्टिकोण के साथ देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है।
- भारतीय रसायनों के निर्यात में वर्ष 2013-14 की तुलना में 2021-22 में 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- पेट्रोकेमिकल्स उद्योग को उच्च कार्बन फुटप्रिंट और समुद्र प्रदूषण को कम करने के लिए एक रणनीति विकसित करनी चाहिए और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

प्लास्टइंडिया 2023 के बारे में:

- प्लास्टइंडिया प्लास्टइंडिया फाउंडेशन के तहत प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो ITPO प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 1-5 फरवरी, 2023 से 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी, सम्मेलन और कन्वेंशन आयोजित करेगा।
- यह भारत को मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोग के लिए प्लास्टिक, कच्चे माल, मशीनरी और उत्पादों से संबंधित संसाधित वस्तुओं की सोर्सिंग के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेगा।

स्रोत: PIB

Important News: State

6. जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम अधिसूचना जारी की

चर्चा में क्यों?

- न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग, जिसके पदेन सदस्य सुशील चंद्रा (मुख्य चुनाव आयुक्त) और के के शर्मा (राज्य चुनाव आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर) हैं, की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई।
- इसके लिए राजपत्र अधिसूचना भी प्रकाशित की गई है।

प्रमुख बिंदु

अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से निम्नलिखित लागू हो जायेंगे:-

- परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(a) तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 60(2)(b) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 47 कश्मीर क्षेत्र के तहत होंगे।
- सहयोगी सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नागरिकों, नागरिक समाज समूहों के परामर्श के बाद, 9 विधानसभा क्षेत्र ST के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 विधानसभा क्षेत्र कश्मीर घाटी में हैं।
- क्षेत्र में पांच संसदीय क्षेत्र हैं।
- परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना है।
- इसलिए, घाटी में अनंतनाग क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र के राजौरी तथा पुंछ को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है।
- इस पुनर्गठन के बाद, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 18 विधान सभा क्षेत्र होंगे।
- यह स्मरण करने योग्य है कि परिसीमन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र

शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से किया गया था।

- परिसीमन आयोग को 2011 की जनगणना के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के भाग-V एवं परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के प्रावधानों के अनुरूप जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम सौंपा गया था।

नोट: पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के माध्यम से गठित किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Award And Honours

7. कान फिल्म बाजार में अब तक का पहला 'सम्मानित देश' बना भारत

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के साथ आयोजित किए जाने वाले **आगामी मार्चे' डू फिल्म में भारत आधिकारिक रूप से 'सम्मानित देश' होगा**।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री ने कहा, 'यह पहली बार है जब मार्चे ' डू फिल्म को आधिकारिक रूप से एक 'सम्मानित देश' मिला है, और यह विशेष फोकस हर साल अलग-अलग देश पर इसके भावी संस्करणों में रहेगा।'
- भारत भी **'कान नेक्स्ट' में सम्मानित देश** है, जिसके तहत 5 नए स्टार्ट अप्स को ऑडियो-विजुअल उद्योग के बारे में बताने का अवसर दिया जाएगा।
- कान फिल्म महोत्सव के इस संस्करण में भारत की सहभागिता का एक अन्य आकर्षण आर माधवन द्वारा बनाई गई फिल्म 'रॉकेट्री' का वर्ल्ड प्रीमियर है।

स्रोत: PIB

Important News: Sports

8. जैन विश्वविद्यालय KIUG 2021 का समग्र विजेता बना

- मेजबान, **जैन विश्वविद्यालय, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) 2021** का समग्र विजेता बना, जिसमें 7 रजत और 5 कांस्य के साथ 20 स्वर्ण पदक शामिल थे।
- लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही। पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रही।
- बेंगलुरु में आयोजित KIUG 2021 के दूसरे संस्करण में लगभग 190 विश्वविद्यालयों के लगभग 3,879 प्रतिभागियों ने 20 विषयों में 257 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) के बारे में:

- यह भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का बहु-खेल आयोजन है, जहां देश भर के विश्वविद्यालयों के एथलीट विभिन्न खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- यह भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ आयोजित किया जाता है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर